connectivity in various regions of our country. While I whole-heatedly appreciate these forward-looking initiatives, I must draw your attention to a similar urgent need in our State of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh, celebrated for its breathtaking natural beauty and serene environment, thrives on tourism, which is a vital pillar of its economy. However, our unique mountainous terrain poses significant challenges to connectivity. This is not only an issue for the influx of tourists eager to experience our State's charm but also a matter of daily life for our residents, especially those living in vast tribal areas where connectivity remains a struggle. At present, civil aviation infrastructure in Himachal Pradesh is not keeping pace with our developmental needs.

Our existing airports require comprehensive renovations and enhanced facilities to cater to rising demand. Furthermore, frequency of flights needs to be increased at all operational airports to ensure that both local communities and visitors can travel with ease. In addition to these measures, I strongly advocate initiation of regular helicopter services to serve the remote and difficult-to-reach areas of our State. Currently, each district is equipped with a helipad; however, these facilities need to be renovated and brought up to modern standards so they can function as reliable lifelines for connectivity.

Mr. Deputy Chairman, Sir, while we appreciate the Government's proactive stance as demonstrated in the current Budget, it is imperative that similar initiatives be extended to Himachal Pradesh. Strengthening our civil aviation infrastructure will not only bolster tourism but also improve the quality of life for our citizens by ensuring more efficient and widespread connectivity.

I, therefore, respectfully urge the Government to consider these proposals for immediate action so that Himachal Pradesh may fully benefit from the nation's commitment to enhanced regional connectivity and sustainable development. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Harsh Mahajan: Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand to establish Multi Model Logistic Park in North Bihar

श्री संजय कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत देश भर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का विकास किया जा रहा है। महोदय, जहाँ एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना के फतुहा में विकसित किया जा रहा है, वहीं नॉर्थ बिहार की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और आर्थिक

विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर एक अतिरिक्त मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया उत्तर बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर विचार करें। यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सड़क, रेलवे और संभावित जलमार्गों सहित कई परिवहन विधाओं के संयोजन का एक केंद्र बनेगा, जो माल के सुचारू रूप और प्रभावी परिवहन को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक वेयर हाउसिंग और एकीकृत कस्टम क्लियरेंस सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर बिहार की नेपाल सीमा से निकटता और कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से सामरिक संपर्क सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इसके साथ ही यह कृषि निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा और देश भर के विभिन्न बिंदुओं से संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। उपसभापति महोदय, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Kumar Jha: Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Dr. John Brittas (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand to make recruitment process for the posts of Post Master and Gramin Dak Sewak in Uttarakhand on the basis of state level cadre

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में एक महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पिछले दिनों संचार विभाग द्वारा उत्तराखंड में अनेक पोस्ट मास्टर्स तथा डाक सेवकों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, इन नियुक्तियों में देश के अनेक बेरोजगारों को नियुक्ति दी गई, परंतु अनेक युवाओं को उत्तराखंड के जटिल पहाड़ी स्वरूप एवं भाषा बोली की दिक्कतों के कारण अपने स्थल पर नियुक्ति नहीं दी गई। महोदय, पूर्व में ये नियुक्तियाँ राज्य के मंडल स्तर कैडर के आधार पर होती थीं तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता था, जो उस क्षेत्र की भाषा और बोली को समझते थे तथा ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिलता था। महोदय, आज देश के सभी डाकघरों को जिस प्रकार से अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, वह कदम स्वागतयोग्य है। उत्तराखंड में भी तकनीकी जानकारी रखने वाले अनेक युवा हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी मनी ऑर्डर पर केंद्रित है, अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय पर पोस्ट मास्टर्स तथा ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति अवश्य पारदर्शी हो, परंतु इसका नियुक्ति कैडर पूर्ववत् ही रखा जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Mahendra Bhatt: Shrimati Maya Naroliya